जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 231 प्रभात हिण्डौन सिटी, सोमवार 22 जून, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

तुषार मेहता 3 साल के लिये फिर सॉलिसिटर जनरल नियुक्त

नई दिल्ली, 21 जून। केन्द्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। यह उनकी तीसरी बार पुनर्नियुक्ति है। इससे पहले दो बार उनका कार्यकाल बढ़ ाया जा चुका है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश के

■ यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे 2018 में सॉलिसिटर जनरल बने थे।

अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने देश के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में तुषार मेहता के पद पर बने रहने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेहता को, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा देने के बाद, अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। केन्द्र सरकार ने बाद में उन्हें 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर के प्रयास से अमेरिका -ईरान वार्ता स्विटजरलैंड में शुरु हुई

बुर्गेनस्टॉक (स्विट्जरलैंड), 21 जून। स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच महत्वपूर्ण वार्ता का नया दौर शुरू हो गया है। इस बातचीत को पश्चिम एशिया में जारी तनाव को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वार्ता प्रक्रिया में कतर की सक्रिय भूमिका सामने आई है, जबकि कुछ रिपोर्टों में अन्य मध्यस्थ देशों के सहयोग का भी उल्लेख किया गया है।

कतर के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि यह संवाद दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों पर व्यापक और स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कूटनीतिक हलकों में इस बैठक को लंबे समय से चली आ रही असहमतियों को कम करने के

■ अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल के कुछ घंटों में समझौते को लेकर अच्छी प्रगति हुई है।

प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि हाल के घंटों में अच्छी प्रगति हुई है और दोनों पक्ष शांति एवं स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ ने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भविष्य में ऐसे पश्चिम एशिया की कल्पना करता है, जहां सहयोग, आर्थिक विकास और स्थिरता को प्राथमिकता मिले।

वैंस के अनुसार, अमेरिकी नेतृत्व क्षेत्र में दीर्घकालिक कूटनीतिक समाधान को बढ़ ावा देना चाहता है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया की राजनीतिक और रणनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर दिए एक बयान में ईरान के साथ संभावित समझौते और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया।

उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जुड़े आर्थिक उपायों पर भी विचार व्यक्त किया, हालांकि वर्तमान युद्धविराम अवधि के दौरान किसी नए शुल्क की संभावना से इनकार किया गया है।

नीट परीक्षा से पूर्व हिसार में छात्रा ने आत्महत्या की

चंडीगढ़ , 21 जून। हरियाणा के हिसार में रविवार को नीट परीक्षा से पहले एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 19 वर्षीय मृतका की पहचान सिमरन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बरवाला क्षेत्र के ढ ाणी खान बहादुर गांव की निवासी थी। हिसार पुलिस को दिए

■ सिमरन ने घर पर रखा कीटनाशक पी लिया था।

बयान में पिता रोहताश ने बताया कि सिमरन मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थी। सिमरन राजस्थान के सीकर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और वह इससे पहले दो बार नीट परीक्षा दे चुकी थी। पहले प्रयास में वह सफल नहीं हो सकी थी, जबकि दूसरी बार परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और पूरी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी में जुटी हुई थी।

रविवार सुबह सिमरन और उसकी मां शकुंतला घर पर ही थीं। सुबह करीब 10 बजे सिमरन को अचानक तेज उल्टियां होने लगीं। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे गांव के एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत की प्राचीन परम्परा योग, अब दुनिया की जीवनशैली का हिस्सा बन गया है- मोदी

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने कोलकाता के रेड रोड पर योग किया

कोलकाता, 21 जून। कोलकाता के रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योगाभ्यास में भाग लिया। उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी, राज्यपाल आरएन रवि, राज्य सरकार के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बसु, विधायक, छात्र-छात्राएं, खिलाड़ी, योग साधक तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के दौरे और योग दिवस के मुख्य आयोजन को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार सुबह रेड रोड पहुंचे और मंच से देशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग सभी को जोड़ने का माध्यम है

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि योग को केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहिये। इसे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिये।

और आज 21 जून दुनिया के सबसे बड़े पर्वों में परिवर्तित हो चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा होने के बावजूद, अब पूरी दुनिया की जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में हिमालय से हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक योग की ऊर्जा दिखाई दे रही है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की भूमि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धरती पर योग दिवस का आयोजन विशेष महत्व रखता है। उन्होंने श्री अरविंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री अरविंद ने अपने पूरे जीवन को योग से जुड़ा बताया था और योग वास्तव में मानव चेतना से जुड़ने का मार्ग है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि योग को केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करता है और मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होर्मुज़ बंद किया तो ईरान पर हमला करेंगे- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे होर्मुज़ पर कब्जा करके खुद टोल वसूलेंगे

वॉशिंगटन, 21 जून। स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक में, जहां एक ओर पाकिस्तान और क़तर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है।

ट्रंप ने साफ-साफ कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने की जुर्रत की, तो उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा, आप इसे बंद करेंगे तो आपके पास कोई देश नहीं बचेगा। आप अपने देश वापस भी नहीं जा पाएंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है। उन्होंने एक

■ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका होर्मुज़ का रक्षक बन सकता है। बदले में वहाँ से निकलने वाले कुल तेल का 20 प्रतिशत अमेरिका अपने पास रखेगा।

कैबिनेट बैठक के दौरान कहा, अगर हमें जरूरत पड़ी, तो हम होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर कब्जा करेंगे। अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं, तो हम खुद वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलेंगे। डॉनल्ड ट्रंप का यह बयान ईरान के उस हालिया कदम के बाद आया है, जिसमें उसने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने की बात कही थी।

ट्रंप ने अमेरिका की भूमिका को एक नए अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य का गार्जियन एंजेल यानी रक्षक बन सकता है। इसके बदले में अमेरिका वहां से निकलने वाले कुल तेल का 20 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेगा। ट्रंप ने साफ किया कि अगर वैश्विक व्यापार को बाधित करने की कोशिश की गई, तो अमेरिकी सेना चुप नहीं बैठेगी। खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखना अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की पुत्री को ईडी ने फिर समन भेजा

कोलकाता, 21 जून। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएमआरएल मनी लॉण्डरिंग मामले में वीणा को दोबारा समन जारी

■ गत 17 जून को ईडी ने वीणा टी से 9 घंटे पूछताछ की थी।

कर 29 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले, ईडी ने 17 जून को उनसे नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। अब एजेंसी ने जांच के दौरान मिले नए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फिर से उन्हें तलब किया है। इस मामले को लेकर केरल की राजनीति भी गरमा गई है और विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद

राशिद का मानना है कि वे मतदाताओं की उम्मीदों पर प्रभावी ढंग से खरे नहीं उतर पा रहे हैं

श्रीनगर, 21 जून। जम्मू-कश्मीर की राजनीति से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामूला लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद इंजीनियर राशिद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने इस बात के संकेत दिए हैं। इंजीनियर राशिद का मानना है कि जिन लोगों ने उन्हें इतना बड़ा जनादेश देकर जिताया, वे उनके बीच रहकर उनकी उम्मीदों पर प्रभावी ढ ंग से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसी वजह से वे पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं।

एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पार्टी

■ अंतिम निर्णय से पहले राशिद की पार्टी एआईपी दो दिन तक बारामूला लोकसभा सीट के 18 विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक व पंचायत स्तर पर जनता का मूड भांपेगी, उसके बाद राशिद अंतिम निर्णय लेंगे।

की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने इस मुद्दे पर लंबी और गंभीर चर्चा की है। इसके बाद यह तय किया गया है कि बारामूला संसदीय क्षेत्र के सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी।

यह पूरी परामर्श प्रक्रिया दो दिनों तक चलेगी। इस दौरान ब्लॉक और पंचायत स्तर के नेता न सिर्फ आपस में चर्चा करेंगे, बल्कि आम जनता और समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच जाकर उनका मूड भी भांपेंगे।

इनाम उन नबी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और दबाव मुक्त रखने के लिए, पार्टी जरूरत पड़ने पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच सीक्रेट बैलेट (गुप्त मतदान) भी करा सकती है। इससे कार्यकर्ता बिना किसी झिझक के अपनी असली राय दे सकेंगे कि इंजीनियर राशिद को सांसद पद पर बने रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता ने साफ किया कि इस पूरी रायशुमारी और वोटिंग का जो भी नतीजा निकलेगा, उससे इंजीनियर राशिद को लिखित में अवगत कराया जाएगा। इसके बाद ही वे कोई अंतिम और ठोस फैसला लेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इंजीनियर राशिद इस्तीफा देते हैं, तो कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।

भाषण के बीच नारेबाजी पर खड़गे ने नाराजगी जताई

बेंगलुरु, 21 जून। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं की नारेबाजी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान लगातार नारेबाजी से असंतुष्ट खड़गे ने कुछ कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए उन्हें "यूज़लैस फेलोज" तक कह दिया।

बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर आयोजित समारोह में खड़गे मंच से संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री डीके

■ कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे।

शिवकुमार के समर्थक लगातार "डीकेशी, डीकेशी" के नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि स्वयं डीके शिवकुमार ने भी कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रही। अपने संबोधन में लगातार बाधा पड़ने से खड़गे ने नाराजगी जताई। खड़गे ने कहा कि यहां इस तरह चिल्लाने से देश आपके हाथ में नहीं आ जाएगा। यूज़लैस फेलोजा।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है।

खड़गे ने कहा कि यह पार्टी को एकजुट करने का कार्यक्रम है। केवल एक नेता के नाम के नारे लगाने से क्या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रविवार को भी जारी रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 21 जून। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का दूसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। सीजेपी का कहना है कि वह रविवार रात को भी

■ सीजेपी ने कहा कि रविवार रात को भी प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रहेगा।

अपना प्रदर्शन जारी रखेगी।

अभियान के प्रमुख अभिजीत दिपके लगातार लोगों से उनके अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। रविवार को दिपके ने दिल्ली से सटे राज्यों के लोगों से जंतर-मंतर पर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल होने का आ ान किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने एक्स पर जारी वीडियो में कहा, "नाओ ऑर नैवर" (अब नहीं तो कभी नहीं)। अगर आज आप लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तो सिस्टम को बदलने और जवाबदेही लाने की जो उम्मीद इस देश में जगी है, वह हमेशा के लिए मर जाएगी।

सीजेपी प्रमुख ने कहा कि पुलिस किसी को रोक नहीं रही है, सभी को अंदर आने दिया जा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे संविधान का पालन कर रहे हैं और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या इज़रायल का अमेरिका से विलग होकर स्वतंत्र विदेश नीति रखना एक खयाली पुलाव है?

इज़रायल की सेना के लगभग सभी हथियार अमेरिका की देन हैं। यह ही हाल गोला बारूद का है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की एक तीखी चेतावनी ने यरुशलम और उससे बाहर लंबे समय से उठ रहे एक सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है-इज़रायल अमेरिकी सैन्य समर्थन पर कितना निर्भर है और यदि यह समर्थन कभी कम कर दिया जाए तो क्या वह उससे निपट पाएगा?

वैंस का संदेश इज़रायली मंत्रिमंडल के लिए सीधा था-अपने सबसे करीबी सहयोगी के खिलाफ मत जाइए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इज़रायल की रक्षा करने वाले अधिकांश हथियार अमेरिका में बनाए और फंड किए गए हैं।

उनकी यह टिप्पणी इज़रायली अधिकारियों द्वारा ईरान के साथ यू.एस. की मध्यस्थता वाली अंडरस्टैण्डिंग के बाद और यू.एस.- ईरान शांति समझौते के बाद आखिरी दो दिनों में बम दागने के बाद पैदा हुए तनाव के बाद आई।

दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ उस 14-सूत्रीय अंतरिम समझौते में है, जिस पर वॉशिंगटन ने तेहरान के साथ हस्ताक्षर किए थे। इज़रायल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत घोषणा कर दी कि इस समझौते का इज़रायल पर कोई प्रभाव नहीं है। वहीं रक्षा मंत्री इज़रायल कैट्ज़ ने सेना को निर्देश दिया कि यदि आवश्यकता पड़े तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर एकतरफा हमले की योजना तैयार की जाए।

इस दिखावे के बावजूद, वास्तविकता यह है कि रक्षा मामलों में पूर्ण संप्रभुता के बजाय एक दूसरे पर गहरी निर्भरता है।

1948 में स्थापना के बाद से इज़रायल को अमेरिका से 130 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता मिल चुकी है। 2019 से अमेरिका फॉरेन मिलिटरी फायनैंसिंग प्रोग्राम के तहत हर वर्ष लगभग 3.8 अरब डॉलर की सहायता दे रहा है, जो इस योजना के तहत किसी भी देश को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इज़रायल को इस धन का अधिकांश हिस्सा अमेरिका निर्मित हथियारों और सैन्य उपकरणों पर खर्च करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि यह पैसा अंततः अमेरिकी कारखानों और रोजगार में ही वापस चला जाता है।

■ अपने संस्थापन से ही, इज़रायल को अभी तक 130 बिलियन डालर की सैन्य सहायता मिली है अमेरिका से।

■ इज़रायल की वायु सेना दुनिया की श्रेष्ठ वायुसेना में गिनी जाती है, पर एफ-15, एफ-16, एफ-35 तथा अपाचे लड़ाकू हवाई जहाज, ब्लैक हॉक्स आदि भी अमेरिकी मूल के हैं। यह ही नहीं, इन आधुनिक विमानों के स्पेयर पार्ट्स भी अमेरिका से आते हैं।

■ इस प्रकार इज़रायल अमेरिका पर आश्रित है, अपनी सेना को "फाइटिंग फिट" रखने के लिए। अगर यह सप्लाई बन्द हो जाये तो इज़रायल की सेना के लिए युद्ध में बने रहना असंभव है।

■ ये हथियार बनाना भी काफी मंहगा ही विकल्प है। इज़रायल ने 1980 के दशक में अपना ही लड़ाकू विमान बनाने का प्रयास किया था, जिसमें उनकी जी. डी. पी. का 20 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ था, पर फिर यह प्रोजेक्ट अधूरा ही छोड़ना पड़ा था, क्योंकि आगे विमान विकसित करने के लिए धन उपलब्ध नहीं था।

■ इस प्रकार इज़रायल की सामरिक व्यवस्था अमेरिका के साथ गुथी हुई है, जिसका विलग होना केवल कल्पना तक ही सीमित है।

■ साथ ही दोनों देश महसूस करते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है तथा, इज़रायल के लिए अमेरिका से जुदा विदेश नीति की कल्पना कभी यथार्थ में तब्दील नहीं हो सकती।

ब्राउन विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, 2023 के अंत से 2025 के अंत के बीच इज़रायल को लगभग 21.7 अरब डॉलर की अतिरिक्त आपातकालीन सहायता भी मिली। इसमें ईरान के साथ हालिया संघर्ष और लेबनान में सैन्य अभियानों की लागत शामिल नहीं है।

दुनिया की सबसे सक्षम वायु सेनाओं में गिनी जाने वाली इज़रायल की वायु शक्ति मूल रूप से अमेरिकी रक्षा उद्योग पर आधारित है। उसके सभी प्रमुख लड़ाकू विमान-एफ-15, एफ-16 और एफ-35 तथा अपाचे हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक और हवाई ईंधन भरने वाले विमान अमेरिका में निर्मित हैं। यहां तक कि नियमित रखरखाव के लिए भी उसे स्पेयर पार्ट्स, इंजन और रडार उपकरणों के लिए अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

गोला-बारूद की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सटीक निशाना लगाने वाली किट, भूमिगत बंकरों को नष्ट करने वाले बम और हाल के अभियानों में इस्तेमाल किए गए छोटे आकार के बम मुख्यतः अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जब इज़रायल ने ईरान की गहराई में स्थित परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की, तब उसके पास आवश्यक भारी क्षमता वाले बम नहीं थे और उसे अमेरिकी सहायता पर निर्भर होना पड़ा।

यहां तक कि इज़रायल की प्रसिद्ध आयरन डोम रक्षा प्रणाली भी, भले ही देश में विकसित की गई हो, अमेरिकी कंपनी आर.टी. एक्स के साथ साझेदारी में बनाई जाती है। अमेरिका ने इस कार्यक्रम में नियमित सहायता से अलग अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके कई प्रमुख इंटरसेप्टर पुर्जे अमेरिका में बनाए जाते हैं और भारी हमलों के दौरान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)